Survey of Projects for Artificial Recharge of Water

4897. SHRI A. T. PATIL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Government of India and/or any State Government has undertaken survey of projects for artificial recharge of water to increase ground water potential;

(b) if so, what are those projects and what is the feasibility of each of them;

(c) whether Government have received the Sina-Man Survey Project Report in respect of the valleys of those rivers; and

(d) if so, what action did Government take on the said report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). The Central Ground Water Board under the Department of Agriculture has undertaken the following projects:—

(i) *UNDP Assisted Ghaggar River Basin Project in Himachal Pradesh, Punjab Haryana, Rajasthan.*

Artificial Recharge Studies as a means of storing surplus water underground for replenishing depleted aquifers were carried out under the UNDP assisted ground water exploration project in Ghaggar River Basin.

Experimental artificial recharge studies by injection method through wells was tried near the Narwana Branch of the Ghaggar River where over-draft had already lowered the Ground Water levels considerably. Induced recharge studies were experimented at Titiona on the bank of the Ghaggar River. As a result of these studies it has been concluded that artificial recharge could be applied as a means of augmenting the ground water resources.

(ii) *Artificial Recharge Studies in Mehsana area, Coastal Saurashtra area, Gujarat.*

The objectives of the Studies is to find out the feasibility of storing the available surface flows of rivers Sabarmati and Banas in ground water reservoirs for utilisation during the lean period for agriculture in Mehsana area and also to examine its effect on counteracting overdraft conditions in Central and South Eastern parts of Mehsana area. Another objective is to find out the effects of such storages on regional ground water quality in coastal Saurashtra.

(c) and (d). The Central Ground Water Board have completed Sina-Man Project. The report of the project is under preparation.

राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र का विकास

4898. श्री **बुद्धि चन्द्र जैन**: क्या ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र के विकास और वहां अकाल की समस्या के स्थायी हल के लिए क्या योजनायें तैयार की हैं;

(ख) इन मरुस्थल वाले जिलों में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितना व्यय किया गया है और अकाल की समस्या का स्थायी हल ढूंढने में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं को और अधिक व्यापक बनायेगी तथा अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिक धनराशि आबंटित करेगी ताकि अकाल की समस्या का एक दीर्घकालीन हल निकाला जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) राजस्थान में रेगिस्तान क्षेत्रों के विकास के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम को वर्ष 1977–78 के अंत में शुरू किया गया था।

तथापि, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए अनेक जिलों को इस समय चल रहे सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जिसे चौथी योजना के दौरान शुरू किया गया था, के अन्तर्गत भी लिया गया है।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न दीर्घकालीन विकास उपायों के माध्यम से रेगिस्तान बनने को रोकना तथा सूखे की तीव्रता को कम करना है।

(ख) 1974–80 (फरवरी, 1980 तक) की अवधि के दौरान राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 48.45 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। यद्यपि दोनों कार्यक्रमों के वृहद घटक एक जैसे ही हैं अर्थात् वनरोपण तथा

चरागाह विकास, सिंचाई संसाधन, कृषि, बागवानी, डेरी, पशुपालन आदि है फिर भी मरुभूमि विकास कार्यक्रम में रेगिस्तान बनने को रोकने पर अधिक बल दिया गया है । मुख्य सूचकों के सम्बन्ध में भौतिक प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) छठी योजना अवधि के लिए विकास की भावी नीति तथा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लिए गए क्षेत्रों के लिए निधियों के आबंटन तैयार किये जा रहे हैं ।

विवरण

राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में भौतिक उपलब्धियां

(क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

1. वह क्षेत्र जिसमें भूमि तथा नमी संरक्षण उपाय किए गए (हजार हैक्टेयर) . . .	41.0
2. संजित सिंचाई सम्भाव्यता (हजार हैक्टेयर) . . .	16.4
3. वनरोपण तथा चरागाह विकास (हजार हैक्टेयर) . .	6.01
4. दुधारू पशुओं का वितरण (संख्या) .	5350
5. दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटियों की स्थापना (संख्या) .	438
6. भेड़ सोसायटियों की स्थापना .	104

(ख) मरुभूमि विकास कार्यक्रम

1. वनरोपण (पौधरोपण, शेल्टर बेल्ट, रेत टीला स्थिरीकरण, सड़क के किनारे पौधरोपण, चरागाह विकास) (हजार हैक्टेयर) . .	25.94
2. भूमि तथा नमी संरक्षण (जल संचयन ढांचे, बान्ध आदि) (हजार हैक्टेयर) . . .	7.72

मध्य प्रदेश में भूमि सुधार सम्बन्धी परिव्यय

4899. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पंचवर्षीय योजना में, मध्य प्रदेश में भूमि सुधार के लिए कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई और वह योजना में शामिल किए गए कुल परिव्यय का कितने प्रतिशत था;

(ख) इस प्रयोजन के लिए वर्तमान योजना में कितनी राशि रखी गई है;

(ग) क्या योजना में रखा गया परिव्यय भूमि सुधार उपायों पर किए जा रहे व्यय के बराबर है; और

(घ) यदि नहीं, तो योजना में कम आबंटन किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भूमि सुधार राज्य का विषय है और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधियों को राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के बजटों में शामिल किया जाता है । तथापि, ऐसी भूमि के विकास के लिए फालतू भूमि के आवंटियों को सहायता देने के उद्देश्य से पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई थी । वित्तीय वर्ष 1974–75 से 1978–79 के दौरान मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को 22.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई थी । यह धनराशि उपर्युक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य को दी गई कुल सहायता का लगभग 1 6 प्रतिशत बनती है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । तथापि, वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए, वर्ष 1980–81 के केन्द्रीय बजट में इस योजना के लिए 3 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है आवंटन सम्पूर्ण देश के लिए रखा गया है । अतः राज्यवार आवंटनों को वितरित क्षेत्र और राज्य सरकार के पास खर्च न की गई निधियों के आधार पर बाद में निर्धारित किया जाएगा ।

(ग) व (घ). जैसा कि भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निधियां राज्य सरकारों द्वारा अपने बजटों में सुलभ की जाती है । जहां तक केन्द्रीय बजट का सम्बन्ध है चालू वर्ष का प्रस्तावित प्रावधान, वर्ष 1979–80 के दौरान वास्तविक व्यय (94.1 लाख रुपये) से काफी अधिक है ।

Sugar Allotted to West Bengal

4900. SHRI NIREN GHOSH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total amount of sugar allotted to West Bengal, month-wise, from November, 1979 to May, 1980;

(b) respective shares of levy sugar and free sale sugar in this total;

(c) total amount of sugar actually made available to the State, month-wise, from November, 1979 to February, 1980;

(d) whether it is a fact that because of non-arrival of sugar from the Centre, West Bengal Government